and setting up vigilance squads to detect cases of theft of energy. Theft of energy has been made a cognizable offence from August, 1986 under the provision of section 39 of Indian Electricity Act, 1910. To motivate the State Electricity Boards and their tmployees to reduce transmission and distribution losses and to increase the energy generation in thermal power stations, separate incentive schemes in the form of cash awards/ shields hve been introduced.

2746. (Transferred to 18th April, 1994)

Cut in Stake by Enron in Dhabol Power Project

2747. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Enron plans cut its stake in Dhabol project of Maharashtra;

(b) if so, the reasons therefor?

(c) what is the present status of Dhabol joint venture project with multinational companies;

(d) what steps|measures have been taken or are proposed to be taken by Government to complete this project according to its time schedule;

(e) whether the Planning Commission has agreed to the allocation of budgetary financial assistance to complate this vital power project in the current financial year; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes Sir. Enron propose o reduce their equity in the project in due course to 50%.

(b) According to the company, this is in line with the practice followed by them for their projects overseas.

(c) The project has been cleared by the Central Electricity Authority subject to cerain conditions. Maharashtra State Electricity Board have entered into a Power Purchase Agreement with the Dabhol Power Company (DPC).

(d) Government of Maharashtra have appointed a Task Force to monitor regularly, the progress of the project.

(e) Since, the project is in the private sector, no funds will be allocated by the Planning Commission.

(f) Does not arise.

गुजरात और महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन में कमी

2748. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी कमी होने का अनुमान है ;

(ख) क्या इस कमी को पूरा करने के लिये प्रस्तावित नयी परियोजनाओं के लिये कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को कैसे पूरा किये जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चौदहवें विद्युत सर्वेक्षण के आधार पर आठवीं योजना (1996–97) के अंतिम वर्ष में

गुजरात और महाराष्ट्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति निम्नवत होने की प्रत्याशा है :–

	गुजरात		महाराष्ट्र	
	व्यस्ततम-कालीन (मे.वा.)	ऊर्जा (मि.कि.-वा.घा.)	व्यस्ततम-कालीन (मे.वा.)	ऊर्जा (मि.कि. वा.घा.)
आवश्यकता . . .	5487	33645	9202	58036
उपलब्धता . . .	3882	27645	8322	52613
कमी . . .	—1685	—6380	—886	—5423
प्रतिशतता . .	—30.7	—17.8	—9.6	—9.3

नौवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित लक्ष्यों के बारे में ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

कमी की मात्रा को किसी स्तर तक सीमित किए जाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में आठवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं अभिज्ञात की गयी हैं :—

स्कीम का नाम	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे. वा.)	आठवीं योजना (1992–97) के दौरान परिकल्पित लाभ (मे.वा.)
गुजरात :		
1. कदाना–2 यूनिट –3 व 4	2×60	120
2. सिक्का विस्तार यूनिट–2	1×70	120
3. कच्छ लिग्नाइट यूनिट–3	1×70	70
4. उमाण सीसीजीटी	3×33+1×45	78
5. सरदार सरोवर ज.वि.प. (16% हिस्सा)	6×200+5×50	232
महाराष्ट्र :		
1. माणिकदोह	1×6	6
2. उज्जैनी	1×12	12

3.	वारना	2×3	16
4.	सूर्या	1×6	6
5.	मंडारदारा–2	1×34	34
6.	दूधगंगा	2×12	24
7.	डिमे	1×5	5
8.	मीरा पीएसएस	1×150	150
9.	कोयना चरण–4	4×250	500
10.	चन्द्रपुर यूनिट–7	1×500	500
11.	उरान डब्ल्यू. एस. पी.	3×120	360
12.	खापरखेडा विस्तार	2×210	420
13.	ट्राम्बे	3×60	180
14.	बीएसईएस (दहानू)	2×250	500
15.	सरदार सरोवर (27% हिस्सा)	6×200+55×50	232

आठवीं योजना के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र को जिन परियोजनाओं की चालू किए जाने की आशा है इनमें से भी गुजरात और महाराष्ट्र को अपने हिस्से की पर्याप्त विद्युत प्राप्त होगी ।

(ख) गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (यूनिट 5–1×210 मे.वा.) और वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (यूनिट 7–1×210 मे.वा.) गुजरात में दो नयी विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने की प्रस्तावना है जिनके लिए कोयला लिकेज की पुष्टि कर दी गयी है बशर्ते गुजरात सरकार कोल इंडिया लि. के द्वारा कोयला खानों के विकास के लिये निधियां उपलब्ध कराएं । महाराष्ट्र के खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र (यूनिट 5 और 6–2×210 मे.वा.) के लिये भी कोयला लिकेज की पुष्टि कर दी गयी है बशर्ते इस परि योजना के लिए प्रवर्तक द्वारा निधियां उपलब्ध करायी जाएं ।

Talks with World Bank for Restructuring SEBs

2749. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank has initiated direct talks with six State Electricity Boards in consultation with Govt. on an agenda to drastically reform the "bankrupt" SEBs and make them financially viable;

(b) if so, what are these six SEBs; and

(c) the progress made so far in the World Bank's plan to reform the SEBs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) World Bank has offered to fund under its Project Preparation Facility; the diagnostic studies of some of the States showing inclination on undertake major structural reforms in the power sector in their States. So far, the Bank has agreed to fund such studies in the States of Haryana, Uttar Pradesh and Orissa. Requests of Governments of Bihar and Rajasthan are under its consideration.